DAINIK JAGRAN, Delhi, 3.10.2024
Page No. 11, Size:(13.77)cms X (14.05)cms.

मेरठ-राजस्थान में बायो गैस प्लांट का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन, गिनाए सीबीजी के लाभ

मिलेगा स्वच्छ ईंधन, किसानों की होगी कमाई

जागरण संवाददाता, मेरठ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में ऐसे छह प्लांटों का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ऐसे प्लांट किसानों की उन्नति का रास्ता खोलेंगे। किसानों के लिए जो पशु बोझ बन जाते थे, खेती या दूध के भी काम नहीं आते थे, वे पशु अब कमाई का साधन बनेंगे। ऐसे प्लांटों को गोबर बेचकर कमाई की जा सकेगी। गोबर-धन योजना गांवों में परिवर्तन ला रही है।

सीबीजी सर्किल कंपनी ने दो वर्ष पहले यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में एमओयू किया था। मेरठ जिले के बहादुरपुर स्थित प्लांट को केंद्र सरकार की गोबर-धन योजना से सब्सिडी प्राप्त हुई है। इसकी क्षमता 15 टन प्रतिदिन उत्पादन की है, लेकिन अभी एक महीने पहले ही उत्पादन शुरू हुआ है। इसलिए अभी उत्पादन तीन से चार टन प्रतिदिन किया जा रहा है। कंपनी के निदेशक अंकुर जग्गी ने बताया कि सीबीजी एक तरह से सीएनजी का उन्नत रूप है। उत्पादन के बाद गैस को हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दिया जाता है। गेल गैस लिमिटेड के साथ भी करार किया गया है।

गोबर और मैली से बनाते हैं गैस : कृषि के अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन होता है। सीबीजी सर्किल कंपनी के प्लांट में प्रमुख रूप से गोबर व चीनी मिल से निकलने वाली मैली का उपयोग किया जाता है। 20 प्रतिशत गोबर व 80 प्रतिशत मैली के अनुपात में मिश्रण होता है।

असम-राजस्थान में चार संयंत्रों का निर्माण : पीएम ने इस दौरान असम में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा चार सीबीजी प्लांट के निर्माण का भी शुभारंभ किया। असम में प्रमुख ओआइएल परियोजनाओं में गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया शामिल हैं। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि भारत के गांवों में अब सैकड़ों बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, पीएम ने राजस्थान के सांचौर जिले के पथमेड़ा स्थित श्री गोधाम महातीर्थ में भी सीबीजी प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया।

सीबीजी प्लांट का दिल्ली से वर्चुअल उद्घाटन करते पीएम मोदी ● वीडियो ग्रैब

मेरठ के बहादुरपुर स्थित कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट की वह मशीन जिसमें गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है ● जागरण

आइआइटियंस ने स्थापित किया प्लांट

आइआइटी कानपुर से इंजीनियरिंग कर चुके ललित जग्गी व कृष्ण मोहन खत्री बचपन के मित्र हैं। 62 वर्ष के मित्र अब इस प्लांट में पार्टनर बने हैं। कृष्ण मोहन अब फ्लोरिडा (अमेरिका) में रहते हैं। ललित के दोनों बेटे अमित व अंकुर तथा कृष्ण मोहन के बेटे हर्षवर्द्धन व बेटी मीना भी इसमें सहयोगी की भूमिका में हैं।

'आदिवासियों को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण हैं हमारी योजनाएं'

जागरण संवाददाता, हजारीबाग : पीएम मोदी ने बुधवार को झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत आदिवासियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए देश के 792 जिलों में से 549 में 79,150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे देश के 65 हजार गांवों के पांच करोड़ से ज्यादा आदिवासी लाभान्वित होंगे।

समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान आदिवासी समाज के कल्याण से जुड़ा है। यह योजना हमारी सरकार में आदिवासियों को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि धरती आबा भगवान बिरसा की धरती से ही योजना शुरू हो रही है। आज गांधी जयंती है। गांधी जी का मानना था कि देश का तभी तेजी से विकास हो सकता है जब आदिवासी समाज का विकास हो।

हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय कैंपस में प्रधानमंत्री ने कुल कुल 83 हजार 700 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण व शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे आदिवासी युवा आगे बढ़ेंगे और उनके सामर्थ्य का लाभ देश को मिलेगा। जोहार के साथ ही उन्होंने भाषण का समापन किया। पीएम मोदी ने हजारीबाग के ही गांधी मैदान में भाजपा की परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार, जमीन की लूट, कोयले की लूट, ट्रांसफर उद्योग, घुसपैठिए और आदिवासियों के मुद्दे को लेकर सोरेन सरकार पर निशाना साधा।

हजारीबाग में बुधवार को भाजपा की परिवर्तन महारैली के दौरान लोगों का अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ● एएनआइ

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 3.10.2024
Page No. 3, Size:(9.49)cms X (8.66)cms.

मेरठ के बायो गैस प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन

जागरण संवाददाता, मेरठ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए देशभर में ऐसे छह प्लांटों का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे प्लांट किसानों की उन्नति का रास्ता खोलेंगे। किसानों के लिए जो पशु बोझ बन जाते थे, खेती या दूध के भी काम नहीं आते थे, वे पशु अब कमाई का साधन बनेंगे। ऐसे प्लांटों को गोबर बेचकर कमाई की जा सकेगी। गोबर-धन योजना गांवों में परिवर्तन ला रही है।

सीबीजी सर्किल कंपनी ने दो वर्ष पहले यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में एमओयू किया था। मेरठ जिले के बहादुरपुर स्थित प्लांट को केंद्र सरकार की गोबर-धन योजना से सब्सिडी प्राप्त हुई है। इसकी क्षमता 15 टन प्रतिदिन उत्पादन की है, लेकिन अभी एक महीने पहले ही उत्पादन शुरू हुआ है। इसलिए अभी उत्पादन तीन से चार टन प्रतिदिन किया जा रहा है। कंपनी के निदेशक अंकुर जग्गी ने बताया कि सीबीजी एक तरह से सीएनजी का उन्नत रूप है। उत्पादन के बाद गैस को हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दिया जाता है। गेल गैस लिमिटेड के साथ भी करार किया गया है।

गोबर और मैली से बनाते हैं गैस : कृषि के अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन होता है। सीबीजी सर्किल कंपनी के प्लांट में प्रमुख रूप से गोबर और चीनी मिल से निकलने वाली मैली का उपयोग किया जाता है। 20 प्रतिशत गोबर तथा 80 प्रतिशत मैली के अनुपात में मिश्रण होता है।

आइआइटियंस ने स्थापित किया प्लांट: आइआइटी कानपुर से इंजीनियरिंग कर चुके ललित जग्गी व कृष्ण मोहन खत्री बचपन के मित्र हैं। 62 वर्ष के मित्र अब इस प्लांट में पार्टनर बने हैं। कृष्ण मोहन अब फ्लोरिडा (अमेरिका) में रहते हैं। ललित के दोनों बेटे अमित व अंकुर तथा कृष्ण मोहन के बेटे हर्षवर्द्धन तथा बेटी मीना भी इसमें सहयोगी की भूमिका में हैं।

पीएम ने कहा, सीबीजी प्लांट से मिलेगा स्वच्छ ईंधन, किसानों की होगी कमाई

मेरठ के बहादुरपुर स्थित कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट की वह मशीन जिसमें गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है। जागरण

असम में चार सयंत्रों के निर्माण का भी शुभारंभ

प्रधानमंत्री ने इस दौरान असम में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा चार सीबीजी प्लांट के निर्माण का भी शुभारंभ किया। असम में प्रमुख ओआइएल परियोजनाओं में गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया शामिल हैं। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि गाय का गोबर हमारे गांवों में बदलाव ला रहा है। भारत के गांवों में अब सैकड़ों बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

DAINIK JAGRAN, Meerut, 3.10.2024
Page No. 2, Size:(33.71)cms X (16.82)cms.

सीबीजी प्लांट से मिलेगा स्वच्छ ईंधन, किसानों की होगी कमाई : मोदी

बहादुरपुर में बायो गैस प्लांट का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन, 15 टन क्षमता का है प्लांट

संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक पर्यावरण सुविधा से मिलेगा अनुदान

जागरण संवाददाता, मेरठ : कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) उत्पादन करने वाले मवाना-किला परीक्षितगढ़ के बीच बहादुरपुर गांव स्थित प्लांट का उद्घाटन गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। सीबीजी एक तरह से सीएनजी का उन्नत रूप है। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने व गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए देश भर के छह ऐसे प्लांटों का उद्घाटन किया गया है। पीएम ने कहा, ऐसे प्लांट किसानों की उन्नति का रास्ता खोलेंगे। किसानों के लिए जो पशु बोझ बन जाते थे। खेती या दूध के भी काम नहीं आते थे, वे पशु अब कमाई का साधन बनेंगे। ऐसे प्लांटों को गोबर बेचकर कमाई की जा सकेगी। गोबर-धन योजना गांवों में परिवर्तन ला रही है।

सीबीजी सर्किल कंपनी ने दो साल पहले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू किया था। इस प्लांट को केंद्र सरकार की गोबर-धन योजना से सब्सिडी प्राप्त हुई है। इसकी क्षमता 15 टन प्रतिदिन उत्पादन की है, लेकिन अभी एक महीने पहले ही उत्पादन शुरू हुआ है। इसलिए अभी उत्पादन तीन से चार टन प्रतिदिन किया जा रहा है। कंपनी के निदेशक अंकुर जग्गी ने बताया कि उत्पादन के बाद गैस को हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दिया जाता है। गेल गैस लिमिटेड के साथ भी करार किया गया है। प्लांट पर आयोजित उद्घाटन समारोह में बागपत से रालोद सांसद डा. राजकुमार सांगवान, मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, डीएम दीपक मीणा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के क्षेत्रीय प्रबंधक कृष्णा कुमार, गेल गैस लिमिटेड के मेरठ क्षेत्र के महाप्रबंधक विनय कुमार उपस्थित रहे।

कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ● वीडियो ग्रैब

गोबर व मैली से बनाते हैं गैस

कृषि के अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन होता है। सीबीजी सर्किल कंपनी के प्लांट में प्रमुख रूप से गोबर व चीनी मिल से निकलने वाली मैली का उपयोग किया जाता है। गोबर एक हिस्सा व मैली दो हिस्सा के अनुपात में मिश्रण होता है।

बहादुरपुर स्थित कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट की वह मशीन जिसमें गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है● जागरण

सीबीजी सर्किल कंपनी के निदेशक अंकुर जग्गी ने बताया कि सर्किल सीबीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट को वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा वित्तीय सहायता योजना के तहत चुना गया है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। इस परियोजना भारत में औद्योगिक अक्षय ऊर्जा के लिए जैविक कचरे के उपयोग पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य बायोगैस तकनीक में नवोन्मेष को अपनाना है। इसका मकसद ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जैविक कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के नए तरीकों को बढ़ावा देना है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटाना है। इसके तहत अनुदान के रूप में कुल बैंक ब्याज को चुकाने के लिए लगभग दो प्रतिशत धनराशि मिलेगी।

MINT, Delhi, 3.10.2024
Page No. 11, Size:(5.74)cms X (13.02)cms.

bp will continue to pursue oil and gas as well as mobility ventures in India with Reliance. BLOOMBERG

bp ends exclusivity with RIL: India head

Global supermajor bp Plc's exclusivity with Reliance Industries Ltd (RIL) has ended but the energy giant will continue to pursue oil and gas as well as mobility ventures in India with the Mukesh Ambani firm owing to an unwritten strategic partnership, bp's outgoing India head Sashi Mukundan said.

bp in 2011 spent $7.2 billion to acquire 30% interest in 23 oil and gas blocks of Reliance. Eastern offshore KG-D6 block was the cornerstone of the deal that also provided for a 10-year exclusivity period which meant that bp would take up energy projects or investments in India only in partnership with Reliance.

The firm has so far invested more than $12 billion across the energy value chain including bringing on stream three new deepwater natural gas projects in KG-D6 that account for one-third of India's gas production. PTI

MORNING STANDARD, Delhi, 3.10.2024
Page No. 10, Size:(24.90)cms X (10.31)cms.

Crude rises as investors see retaliation from Israel

RAKESH KUMAR @ New Delhi

CRUDE oil prices in the international market rose sharply on Wednesday following a missile attack by Iran on Israel. Brent crude futures, which had been trading near $70 a barrel for the past three weeks, rose by 4% to $75.96 a barrel at 4:30 PM IST.

West Texas Intermediate saw a rise of 3.57%, trading at $72.32 a barrel. The major rise in global crude oil prices is driven by investor concerns over potential retaliation by Israel and its impact on global oil supply. Experts believe if tensions escalate further, crude prices could rise significantly in the coming days. Another concern is that Iran borders the Strait of Hormuz, a narrow choke point through which OPEC+ members, including Saudi Arabia and the UAE, export energy. There is a chance of disrupting shipping through the strait if the conflict escalates.

"Crude prices have risen owing to increase in geo-political risk premium as Israel may retaliate against Iran which may snowball into a larger conflict affecting other crude producers and important trade routes such as Strait of Hormuz. However, it is difficult to predict as to how this conflict pans out and accordingly the eventual impact on crude prices," said Prashant Vasisht, VP & co-head, corporate ratings, ICRA.

> **Crude prices have risen owing to increase in geo-political risk premium as Israel may retaliate against Iran which may snowball into a larger conflict affecting other crude producers**
>
> Prashant Vasisht, VP & co-head, corporate ratings, ICRA

The attack on Israel was reportedly in response to the killing of Sayyed Hassan Nasrallah, the powerful leader of Lebanon's militant group Hezbollah. Iran, a member of the OPEC+ group, is one of the world's top oil producers, with data showing it produced over 3.3 million barrels per day in August—the highest output in five years, as per the Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). The country exports about half of its production, which represents nearly 2% of global supply.

BUSINESS STANDARD, Delhi, 3.10.2024
Page No. 2, Size:(24.90)cms X (13.77)cms.

Exclusivity ends but BP to continue with Reliance

Global supermajor BP's exclusivity with Reliance Industries (RIL) has ended but the energy giant will continue to pursue oil and gas as well as mobility ventures in India with the firm owing to an unwritten strategic partnership, BP's outgoing India Head Sashi Mukundan said. BP in 2011 spent $7.2 billion to acquire 30 per cent interest in 23 oil and gas blocks of Reliance. Eastern offshore KG-D6 block was the cornerstone of the deal that also provided for a 10-year exclusivity period. PTI

ECONOMIC TIMES, Delhi, 3.10.2024
Page No. 13, Size:(18.12)cms X (10.25)cms.

German Co Roped in for Safety Audit of H2 Train

Trial runs for first hydrogen train targeted for Dec

Twesh Mishra

New Delhi: The Indian Railways has roped in Germany's TUV-SUD to conduct a third-party safety audit of the country's first hydrogen train.

According to officials aware of the plan, trial runs for hydrogen powered rolling stock are expected to begin in December 2024.

Besides the hydrogen-powered trains, five Hydrogen Fuel Cell-Based Tower Cars (maintenance vehicles), estimated to cost 10 crore per unit, are also being developed.

"The Indian Railways (IR) will have 35 trains under the Hydrogen for Heritage initiative at an estimated cost of 80 crore per train with another 70 crore investment in ground infrastructure per route on various heritage or hilly routes," the official told ET.

With this, India will become the fifth country in the world, after Germany, France, Sweden, and China, to operate Hydrogen-powered trains.

"The System integration Unit battery and two fuel unit synchronization tests have been successfully done," the official said.

Another pilot project for retrofitting of Hydrogen Fuel Cells on the existing Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) rake, along with ground infrastructure, is also underway. This train is planned to be run on the Jind –Sonipat section of Northern Railway. "Integration of prototype train is planned in Integral Coach Factory, Chennai," the official added. Hydrogen for this train in Haryana is said to be supplied from a 1-megawatt (MW) Polymer electrolyte membrane (PEM) electrolyser at Jind.

A statement from GreenH Electrolysis, which runs the production unit, said this electrolyser will operate round the clock producing approximately 430 kg/day of hydrogen

"The refuelling infrastructure at Jind will also have a 3,000 kg hydrogen storage, hydrogen compressor, and two hydrogen dispensers with pre-cooler integration, allowing for quick refuelling of the trains," the statement said.

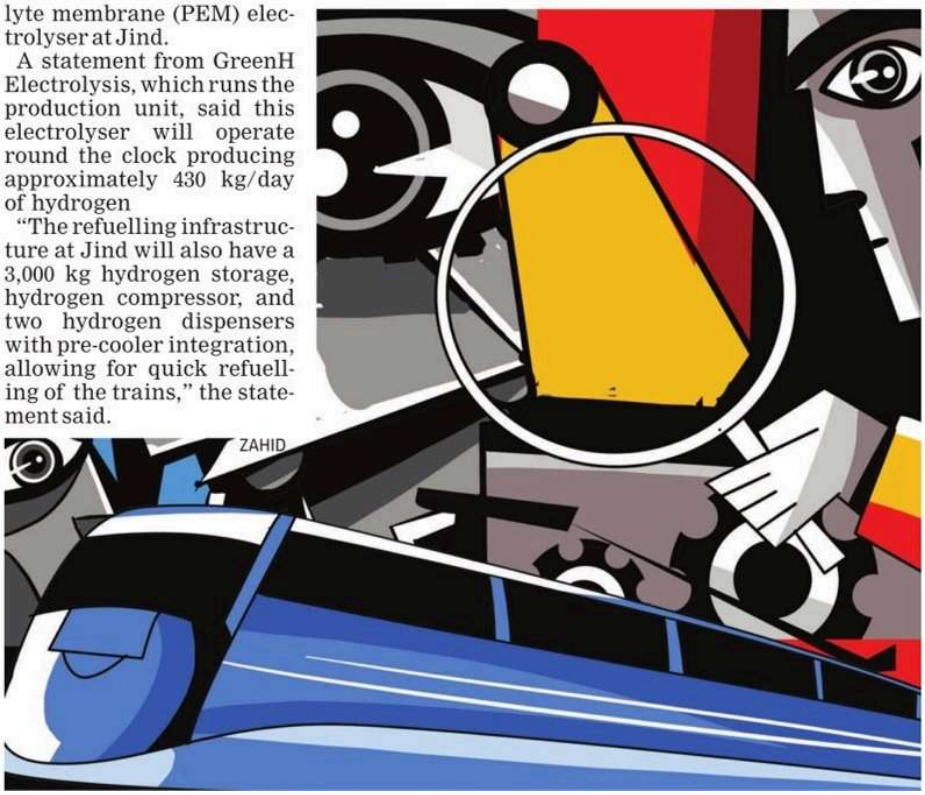

INDIAN EXPRESS, Delhi, 3.10.2024
Page No. 13, Size:(13.74)cms X (26.29)cms.

India's Saudi oil imports jump as Riyadh looks to claw back share lost to Russia

SUKALP SHARMA
NEW DELHI, OCTOBER 2

INDIA'S CRUDE oil imports recovered sequentially in September as a few under-maintenance refineries are slated to come back on stream in October. Notably, the sequential recovery in import volumes was led by Saudi Arabia, which has reduced its prices in a bid to claw back some of its lost market share in India, according to ship tracking data and industry watchers. Oil imports from Russia—New Delhi's largest source market for oil—also rose in September as India's overall oil demand expanded.

As refiners usually buy crude in advance for their requirements of the next couple of months, India's oil demand had softened in August in the run-up to the peak refinery maintenance season in September. With most of the refinery units undergoing maintenance expected to start operating from this month, there was an uptick in import volumes in September. Oil imports could rise further in October as the maintenance season would give way to high refinery run rates required to meet the festival season fuel demand. Oil imports from Saudi Arabia in September jumped 39.8 per cent month-on-month to 0.73 million barrels per day (bpd), the highest since March this year, per provisional vessel tracking data from commodity market analytics firm Kpler. Riyadh had been bleeding market share in India's oil import basket due to the relatively higher price of its oil than the competing crude grades from other major suppliers—Russia and Iraq. In fact, in June, India's Saudi Arabian oil imports had crashed to a multi-year low of 0.42 million bpd.

Riyadh now appears to be making an attempt to win back part of its lost market share by offering its oil at a lower price. Market participants expect import volumes from Saudi Arabia to rise further in the coming months, so long as Riyadh is able to keep its barrels competitive for price-sensitive Indian refiners. "The prospect of losing India is one of the main worries for Saudi Arabia ... Many had expected that India would cut down on Russian barrels, but it didn't. Now the risk is that it (oil imports from Russia) might get even higher," said Viktor Katona, head of crude analysis at Kpler. The prospect of even higher oil imports from Russia is due to expectations of Indian refiners inking bigger term deals for Russian oil for the coming year.

File

INDIA'S TOP CRUDE OIL SUPPLIERS IN SEPT

Country	Volume	Change vs August
Russia	1.88 mn bpd	6.4%
Iraq	0.87 mn bpd	3.3%
Saudi Arabia	0.73 mn bpd	39.8%
UAE	0.49 mn bpd	18.6%

Source: Kpler

According to sources in India's refining sector, if Saudi Arabia gets more aggressive in its effort to increase market share in India, Indian refiners stand to gain as it would lead to increased competition among suppliers. This could force other major suppliers like Russia and Iraq to offer better prices to Indian buyers. India's import of Russian crude rose 6.4 per cent over August to 1.88 million bpd, accounting for a staggering 40.2 per cent of New Delhi's overall crude oil imports of 4.68 million bpd in September, which were 5 per cent higher sequentially. Iraq, India's second-largest source market for crude oil, supplied 0.87 million bpd, accounting for 18.7 per cent of New Delhi's total oil imports in September. Saudi Arabia improved its market share to 15.5 per cent in September from 11.7 per cent in August.

Prior to the war in Ukraine, Iraq and Saudi Arabia were the top two suppliers of crude oil to India. But as the West started weaning itself off Russian energy supplies following Moscow's February 2022 invasion of Ukraine, Russia started offering discounts on its crude and Indian refiners started snapping up the discounted barrels. As the world's third-largest consumer of crude oil with a high import dependency level of over 85 per cent, India is extremely sensitive to oil prices. Although trade sources have indicated that discounts on Russian crude have shrunk over time, Indian refiners have evidently remained keen on buying Russian oil as given the high import volumes, even lower discount levels lead to significant savings.

Interestingly, India's oil imports from its fourth-largest supplier—the United Arab Emirates—rose 18.6 per cent month-on-month to 0.49 million bpd in September, the highest since June 2022. According to Katona, the uptick is driven by Indian refiners' growing appetite for UAE's Murban crude, which is increasingly becoming the light grade of choice for bending with Russia's flagship medium-sour crude Urals. The grade is also the mainstay of India's Russian oil imports.

BUSINESS STANDARD, Delhi, 3.10.2024
Page No. 4, Size:(13.18)cms X (42.12)cms.

India, Brazil push to finalise GBA charter by yr-end

SUBHAYAN CHAKRABORTY
New Delhi, 2 October

India and Brazil have taken up the delay in setting up the Global Biofuel Alliance (GBA) headquarters and establishing a charter, and agreed to establish both by the end of the current year, sources said.

The issue was discussed during Petroleum Minister Hardeep Singh Puri's meeting with his counterpart in Brasilia last month, they added. The GBA was launched on September 9, 2023, on the sidelines of the G20 Summit in New Delhi.

But more than a year later, it remains without a charter, a fixed governance structure, or a permanent secretariat.

"Both sides recognised the importance of quickly resolving the pending work on the GBA. A year-end date is being tentatively eyed for clearing the pending work on securing a headquarters, and establishing a charter," an official source said.

However, the multi-stakeholder alliance of governments, international organisations and industries has adopted a work plan.

Focussing on assessing country landscapes, drafting policy frameworks, and conducting biofuel workshops were identified as immediate goals for the GBA.

These goals were discussed at a key meeting of the body held on the sidelines of the G7 deliberations in Brazil in April, a Petroleum and Natural Gas Ministry official said. India has suggested three potential workstreams — to support biofuel trade, increase awareness about them, and identify support mechanisms for enhanced adoption of biofuels. "These developments also came up during the latest visit. Both countries feel there has been good progress on the segmented approach towards GBA goals that has been taken so far," the official added.

Interest growing

The GBA aims to expedite uptake of biofuels worldwide, set standards for biofuel, expand the size of formal biofuel markets and better map demand and supply.

India and Brazil were the main drivers of the 24-nation grouping, which had seen 24 diverse countries, from Singapore, Argentina, and UAE, to Mauritius and Bangladesh signing up.

Among the G7 nations, Italy and the United States are part of the alliance.

While major energy producers such as Russia, China and Saudi Arabia have remained unconvinced of the merits of joining the bloc, it has generated special interest from African nations.

Apart from G20 member South Africa, non-G20 nations like Kenya and Uganda also make up the list, while Tanzania is keen on joining, sources have said.

Caribbean island nation Jamaica has been the latest to show an interest to join the GBA, the Ministry of External Affairs had said on Tuesday.

According to the International Energy Agency (IEA), biofuels have the potential to grow by 3.5-5-times by 2050. This is due to the net-zero targets, thus creating a huge opportunity for India.

QUICK RUNDOWN

- Global Biofuel Alliance, launched in 2023, still lacks a formal governance setup
- India suggested workstreams to boost biofuel trade and adoption
- GBA has 24 member nations, with growing interest from Africa and the Caribbean
- Biofuels could grow 5x by 2050, creating big opportunities for India

ASSAM TRIBUNE, Guwahati, 3.10.2024
Page No. 10, Size:(24.90)cms X (18.00)cms.

Jorhat Press Club urges PM to reconsider decision

Centre's approval to carry out oil, gas exploration near Hollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary

STAFF CORRESPONDENT

JORHAT, Oct 2: The Jorhat Press Club (JPC) have urged the Prime Minister Narendra Modi to reconsider the decision of granting approval by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change to Vedanta-owned Cairn Oil and Gas to carry out exploration and drilling activities on 4.49 hectares plot of land which is close to the Hollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary located in Jorhat district.

In a memorandum to the Prime Minister, through the Jorhat DC office on Monday, the JPC observed that the proposed oil and gas exploration activities may be at a distance of 13 kms from the 20.98 sq km sanctuary, which houses the endangered Hoolock Gibbon, the only ape species found in India, but the site falls within the contiguous Dissoi Valley Reserve Forest, which is also an important eco-sensitive zone and an elephant corridor.

Stating that several organisations and individuals too have voiced concern over the said decision of the Central Government and have expressed apprehension of adverse environmental impact in the region and pose a threat to Hoolock Gibbons, the memorandum said, "The JPC is of the opinion that such proposed exploration and drilling activities at the place will disturb the eco-system and ultimately destroy the biodiversity."

The memorandum requested the Prime Minister to look into the matter and take steps to immediately halt the process of proposed exploration activities of Vedanta's Cairn and Gas Company near the wildlife sanctuary.

Further, the memorandum also demanded the immediate removal of the railway track which passes through the sanctuary.

"The NF Railway have further exacerbated the matter by lighting up the track purportedly not to kill elephants which stray onto the tracks, but the strong lights are likely to cause disturbance to the wildlife housed in this fragile eco-system. The NF Railway may be asked to lay a new track which avoids cutting through the sanctuary and immediately remove the lights," the memorandum mentioned.

TIMES OF INDIA, Delhi, 3.10.2024
Page No. 21, Size:(4.00)cms X (3.72)cms.

Oil rises as Israel vows payback for Iran strike

Oil extended its rally as Israel vowed to retaliate against Iran following its barrage of about 200 missiles, raising the risks to crude supplies from the region. The West Texas Intermediate climbed about 2% to top $71 a barrel, building on a 2.4% advance on Tuesday. BLOOMBERG

MILLENNIUM POST, Delhi, 3.10.2024
Page No. 9, Size:(17.12)cms X (12.96)cms.

OPEC+ panel sticks to output policy, doubles down on compliance by member countries

LONDON/DUBAI: A meeting of top OPEC+ ministers has kept oil output policy unchanged including a plan to start raising output from December, while also emphasising the need for some members to make further cuts to compensate for overproduction, *Reuters* reported.

Several ministers from the Organization of the Petroleum Exporting Countries and allies led by Russia, or OPEC+ as the group is known, held an online joint ministerial monitoring committee meeting (JMMC) on Wednesday.

"The JMMC emphasized the critical importance of achieving full conformity and compensation," OPEC said in a statement after the meeting. "Furthermore, the Committee will continuously assess market conditions."

Oil prices dropped below $70 a barrel in September for the first time since 2021, but

have since rallied above $75 on concerns a possible escalation in the Middle East following Iran's military attack on Israel could disrupt output from the region.

OPEC+ is cutting output by a total of 5.86 million barrels per day (bpd), or about 5.7 per cent of global demand, in a series of steps agreed since late 2022.

The group plans a 180,000 bpd increase in December as part of a gradual unwinding of its most recent layer of voluntary cuts extending into 2025.

The hike was delayed from October after prices slid.

Countries' compliance was in focus at the meeting, sources who attended told *Reuters*, and is expected to remain so in coming weeks, particularly that of Iraq and Kazakhstan.

Those nations have promised what are known as compensation cuts of 123,000 bpd in September and more in later months to make up for their previous over-production.

Iraq, Kazakhstan and Russia told the meeting that they had delivered on their promised cuts in September, the OPEC statement said.

But this will have to be verified by the second week of October by secondary sources - the consultancies and price reporting agencies that the group uses for determining its members' output levels, the statement added.

An OPEC+ source told *Reuters* last week that clarity on whether the compensation cuts were made in September would allow the December increase to go ahead.

However, a lack of compliance could prompt Saudi Arabia and others to raise output even faster from December, analysts said.

"If they fail to comply, we can envision a swifter sunsetting of the voluntary cuts," Helima Croft of RBC Capital said in a report.

The joint ministerial monitoring committee meeting, which groups the oil ministers from Saudi Arabia, Russia and other leading producers, usually meets every two months and can make recommendations to change policy.

It will hold its next meeting on Dec. 1, ahead of a full meeting of OPEC+. AGENCIES

FREE PRESS JOURNAL, Mumbai, 3.10.2024
Page No. 18, Size:(14.18)cms X (13.11)cms.

GAU SEVA IN GWALIOR: Modi inaugurates gaushala virtually alongwith other projects to the tune of Rs 685 cr in state

PM inaugurates country's first modern gaushala

Our Staff Reporter
BHOPAL

Prime Minster Narendra Modi virtually inaugurated Gwalior's 'Lal Tipara Gaushala' with 100 ton capacity bio CNG plant on the occasion of Swachhata Diwas on Wednesday. As per officials, it is the country's first modern and self-reliant gaushala.

PM Modi also inaugurated and laid the foundation stone of various development projects of Rs 685 crore across Madhya Pradesh under the Swachh Bharat Mission and AMRUT Yojana. He was participating in the programme from Delhi where the main function of Swachh Bharat Diwas 2024 was held. The day also marked the culmination of Swachhata Pakhwada.

Chief Minister Mohan Yadav, Ministers and other elected representatives attended the programme via video conference at Kushabhau International Convention Centre. Yadav expressed gratitude to PM over the development works worth Rs 685 crores.

CM Mohan Yadav watches PM Narendra Modi delivering speech on concluding Swachhata Pakhwada on Wednesday

Speaking on the occasion, Yadav said that grand gates will be constructed on the routes of Bhopal and will be named after great personalities- Lord Ram, Raja Bhoj, king Vikramaditya, King Ashok etc- who have association with the state's history. He said that all help will be provided to 'Namo Upvan' being developed by Bhopal Municipal Corporation. The CM also transferred Rs 63.45 lakh into the accounts of 2,115 Safai Mitra of Ujjain as the city of Mahakal has received three star rating under Cleanliness Survey 2022. Yadav flagged various vehicles of Bhopal Municipal Corporation including 125 new Door to Door CNG Vehicles, 6 new hook loader, one litter picking machine. He added that by the inspiration of PM, more than 42, 500 cleanliness activities were organized in 413 local bodies of the state.

Self reliant gaushala

The 'gaushala', or cow shelter, with the Bio-CNG plant that can produce three tonnes of natural gas per day using 100 tonnes of cow dung, has been set up in collaboration with the Indian Oil Corporation (IOC), an official said. It is India's first modern and self-reliant gaushala, he said. The plant will also produce 20 tonnes of high-quality organic manure, the official said, adding the IOC will assist in the operation and maintenance of the plant.

MILLENNIUM POST, Delhi, 3.10.2024
Page No. 6, Size:(21.26)cms X (15.35)cms.

PM Modi inaugurates Gaushala with bio-CNG Plant, launches projects worth Rs 685 cr in MP

Sanitation workers are the backbone of public health, says MP Chief Minister Yadav

SATYAPRAKASH SHARMA

BHOPAL: Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated the 'Lal Tipara Gaushala' along with a bio-CNG plant in Gwalior and launched various development projects worth Rs 685 crore for civic bodies in Madhya Pradesh on Wednesday.

The inauguration took place on Swachhta Diwas, observed every year on October 2, in the honour of Gandhi Jayanti. On this occasion, PM Modi inaugurated the country's first advanced and self-reliant gaushala (cow shelter) in Gwalior. The event also marked the launch of a 100 TDP (ton per day) capacity bio-CNG (compressed natural gas) plant based on cattle dung, at a cost of Rs 32 crore.

The bio-CNG plant, capable of producing three tonnes of natural gas per day from 100 tonnes of cattle dung, has been established in collaboration with the Indian Oil Corporation Limited (IOCL) under the CSR (Corporate Social Responsibility) provisions of the Companies Act, 2013. In addition to producing natural gas, the plant will also generate 20 tonnes of high-quality organic manure. IOCL will assist in both the operation and maintenance of the facility. The Gwalior Municipal Corporation (GMC), which operates the gaushala, contributed Rs 5 crore towards the plant's construction.

Additionally, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones for various development projects worth Rs 685 crore across civic bodies in Madhya Pradesh. These projects are part of the Swachh Bharat Mission and AMRUT Yojana.

Chief Minister Mohan Yadav attended the programme via video conference from Bhopal, where the closing ceremony of the Swachhata Hi Sewa Pakhwada was being held.

The Pakhwada, which began on September 17, the birthday of PM Modi, concluded on October 2 with the birth anniversary of Mahatma Gandhi.

In his address, CM Yadav praised the Prime Minister for launching the Swachh Bharat Abhiyan a decade ago, calling it a "commendable step." He remarked: "Sanitation workers are dedicated to keeping us healthy. Their work is challenging and requires great courage, much like soldiers who sacrifice their lives to protect the country."

The Chief Minister emphasised that a commitment to cleanliness is the truest tribute to Mahatma Gandhi. He also highlighted PM Modi's initiative to construct toilets in every village, which has brought significant relief to women across the country.

CM Yadav announced that more than 42,500 cleanliness activities were organised in 413 urban bodies throughout the state, with massive public participation during the Swachhata Hi Sewa Pakhwada. He assured that the state government would extend all possible support to Namo-Upvan.

During the event, the Chief Minister honoured individuals and organisations that excelled in the Swachhata Hi Sewa-2024 campaign. He also virtually interacted with Safai Mitras from Ujjain and commended their dedication to their work.

Furthermore, CM Yadav distributed compassionate appointment certificates to the dependents of 26 employees of the Bhopal Municipal Corporation who had died while on duty. The Chief Minister also performed a virtual bhoomi pujan for sewerage and water supply projects in 19 urban bodies across the state.

MP CM Mohan Yadav paying tributes to Mahatma Gandhi PIC/MPOST

Takeaways

- CM Yadav praised the Prime Minister Modi for launching the Swachh Bharat Abhiyan a decade ago, calling it a "commendable step"
- The CM emphasised that a commitment to cleanliness is the truest tribute to Mahatma Gandhi
- He assured that the state government would extend all possible support to Namo-Upvan

MINT, Delhi, 3.10.2024
Page No. 2, Size:(14.99)cms X (13.97)cms.

Push to stop govt from suing itself

Manas Pimpalkhare
manas.pimpalkhare@hindustantimes.com
NEW DELHI

This renewed push follows the law ministry's recognition of escalating legal costs involving government bodies. ISTOCKPHOTO

Caught in a cycle of costly legal battles, the government plans to roll out a new national litigation policy aimed at curbing legal expenses, particularly in cases where the government is effectively suing itself, according to two officials.

The policy, still under development, will focus on disputes between government entities, such as public sector undertakings (PSUs), which have long been a financial burden on the administration.

The efforts to review litigation between two PSUs or between a PSU and the central government have been age-old. For instance, in 1991, the Supreme Court noted, "Public sector undertakings of central government and the union of India should not fight their litigations in court" in a dispute between state-run oil producer ONGC and the Collector of Central Excise.

This renewed push follows the law ministry's recognition of escalating legal costs involving government bodies. Law and justice minister Arjun Ram Meghwal signed off on the policy in June, shortly after taking office, as part of broader efforts to rein in these expenditures.

"For instance, consider two PSUs with similar mandates locked in a tender dispute. Both are ultimately owned by the government of India. The national litigation policy will address such cases," said one of the officials.

The policy, still under development, will focus on disputes between govt entities, such as PSUs

The rollout comes as India's judiciary grapples with an overwhelming backlog of cases. As of 2 October, over 50 million cases remain unresolved, including nearly 5.6 million civil suits and 27.2 million criminal cases in district courts alone, according to data from the National Judicial Data Grid. High courts are similarly overburdened with more than 2.5 million pending cases.

The profitability of PSUs is often at stake in such disputes. For instance, in March 2024, state-run Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) won a dispute against the union of India over freight charges worth a little over ₹1.5 crore. In the dispute, the Indian Railways - yet another state-run institution—had billed IOCL for moving freight for 444km.

However, after revisions in the way the Railways calculated distances, the distance to be covered narrowed to 334km. IOCL moved the court against the Railways, and sought a refund for the distance not covered—roughly 110 km—and won the case.

In this matter, IOCL had already emerged victorious before the Allahabad High Court, before Indian Railways appealed it to the Supreme Court—adding legal costs to both sides, according to the judgment. The apex court had to use the law laid down in a 1996 case between the Union of India and Steel Authority of India Ltd (SAIL) to resolve this dispute worth about ₹1.3 crore.

This is not the first time the government has sought to manage its legal liabilities. The government, the country's biggest litigant, has previously attempted to implement cohesive national litigation policies in 2010 and 2015, according to public documents.

For an extended version, visit livemint.com

FINANCIAL EXPRESS, Delhi, 3.10.2024
Page No. 11, Size:(24.90)cms X (14.66)cms.

Russian crude supplies to India rebound in Sept

ARUNIMA BHARADWAJ
New Delhi, October 2

RUSSIA REGAINED THE slot of largest crude supplier to India in September with imports from the country registering an increase of 11.5% to 1.79 million barrels per day against 1.61 million barrels per day in August, data from Vortexa showed. In August, India's import of Russian crude oil had decreased 17% on month due to lower supplies from the country and lower demand as many domestic refineries went under planned maintenance.

In September, Indian refiners imported more crude oil from Iraq and the West Asia. Russia remained the top supplier last month with its share in the country's crude import basket at 38%. Imports from Iraq rose by 16% on month at 894,057 barrels per day in September, accounting for 19% of the country's total crude oil imports. In August, imports from Iraq accounted for 18.5% of the country's total imported crude oil volume. Imports from Saudi Arabia increased by 37% to 688,882 barrels per day in September from 501,048 barrels per day in August.

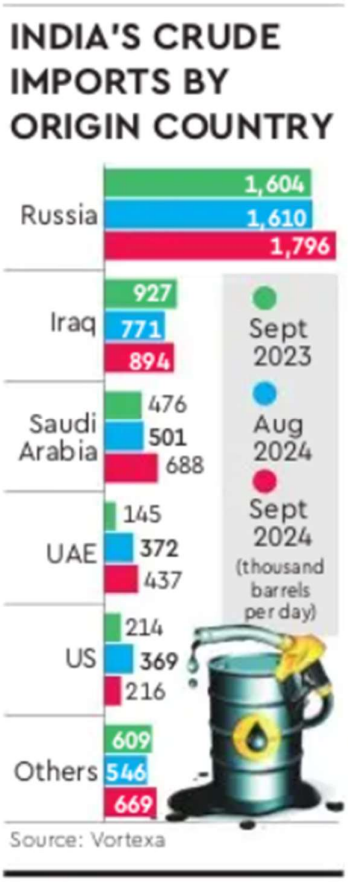

"Russian crude arrivals into India are up 12% month-on-month in September, as lower imports from China and Turkey made more supplies available to India. India has also raised imports from the Middle East to supplement its overall higher crude import demand as refineries ramped up runs," said Serena Huang, head of APAC analysis at Vortexa. The country imported a cumulative of 4.70 million barrels per day of crude oil in September, up from 4.17 million barrels per day in August, as per the data.

Going ahead, analysts expect Russian crude oil supplies to remain robust towards the beginning of the fourth quarter of the fiscal due to anticipated increase in the demand amid competitive pricing as compared to other suppliers.

"Russia will likely maintain its market share in India by keeping its crude attractively priced compared to its rival Middle East grades. The remaining of India's crude import demand will be fulfilled by its term volumes with Middle East producers and spot barrels from Middle East and other Atlantic Basin suppliers," Huang said.

MINT, Delhi, 3.10.2024
Page No. 10, Size:(7.45)cms X (33.58)cms.

Saudi minister warns of $50 oil as OPEC+ members flout production curbs

Benoit Faucon, Summer Said & Anna Hirtenstein

Prince Abdulaziz bin Salman, oil minister, Saudi Arabia. REUTERS

The Saudi oil minister has said that prices could drop to as low as $50 per barrel if so-called cheaters within OPEC+ don't stick to agreed-upon production limits, according to delegates in the cartel.

The statements were interpreted by other producers as a veiled threat from the kingdom that it is willing to launch a price war to keep its market share if other countries don't abide by the group's agreements, they said.

Key members of an alliance made of the Organization of the Petroleum Exporting Countries and its allies, together known as OPEC+, are set to discuss whether to ease production curbs in December at a scheduled online gathering Wednesday.

After Iran launched missiles at Israel on Tuesday, oil prices climbed after weeks of steady declines. Brent crude, the international benchmark, gained as much as 5% before settling at 2.4% higher at just under $70.

There are fears in the West that a wider war could choke oil exports from the Gulf that pass through the Strait of Hormuz, which borders Iran, and push prices higher.

But geopolitical tensions have persisted for months without meaningful effect on oil prices, and the declines have been frustrating for Saudi officials in part because other cartel members have flouted plans to limit production for much of this year.

During a conference call last week, Prince Abdulaziz bin Salman, the oil minister of OPEC kingmaker Saudi Arabia, warned fellow producers prices could drop to $50 a barrel if they don't comply with agreed production cuts, according to OPEC delegates who attended the call.

They said he singled out Iraq, which overproduced by 400,000 barrels a day in August, according to data provider S&P Global Ratings, and Kazakhstan, whose production is set to rise with the return of the 720,000-barrels-per-day Tengiz field.

The Saudi message was "there is no point in adding more barrels if there isn't room for them in the market," said a delegate who attended. "Some better shut up and respect their commitments toward OPEC+."

The Saudi oil ministry didn't respond to a request for comment.

Oil prices have been on a downward slope in recent months, with major benchmarks losing around 16% last quarter. This comes despite the OPEC+ coalition's efforts to stabilize markets through production cuts. The group put forward multiple extensions to these curbs and yet prices dropped further.

The group's production cuts mean their share of the oil market has shrunk. This year it reached 48%, down from 50% in 2023 and 51% in 2022, data from the IEA showed. Competition is set to heat up further next year.

Planned production increases in the U.S., Guyana and Brazil are expected to add over 1 million barrels a day to global oil supply. Brazil joined the OPEC+ group this year but said it won't participate in the output cuts.

Some cartel members that signed on to the cuts have pumped more barrels than they promised, rendering the supply curbs less effective. In addition to Iraq and Kazakhstan, Russia also produced more than its quota this year through July, according to Aug. 8 data from S&P Global.

Despite rising geopolitical tensions, prices are languishing below $75 a barrel—their lowest level in nine months—largely due to slowing economic growth. Saudi Arabia needs prices at $85 per barrel to help fund its economic transformation, analysts say.

The weak prices forced OPEC+ members to delay a production increase for two months following a virtual meeting last month until December. The group had originally agreed in June to start easing voluntary cuts in October.

The kingdom has shown in the past it can open up the spigots if it feels other producers are taking advantage of its efforts to defend oil prices.

Saudi Arabia initiated a price war on oil with Russia in March 2020. The kingdom's decision to pump to record levels amid the Covid pandemic facilitated a 65% quarterly fall in the price of oil to 17-year lows, with some prices in the U.S. turning negative for the first time ever.

Another move by Saudi Arabia to boost production to punish other producers led to a collapse of oil prices to below $10 per barrel in 1986.

THE WALL STREET JOURNAL.

©2024 DOW JONES & CO. INC

feedback@livemint.com

MINT, Delhi, 3.10.2024
Page No. 1, Size:(16.69)cms X (16.51)cms.

West Asia conflict casts a shadow over India, world

In case of an all-out war, economy, market could face shocks, while oil prices surge

Rhik Kundu, Nehal Chaliawala & Gireesh Chandra Prasad

NEW DELHI/MUMBAI

India could brace for trade and stock market shocks, costlier crude and shipping, fewer jobs for Indians in West Asia and a drag on growth momentum, experts said, as Iran's direct attack on Israel and the latter's missile strikes on neighbouring Lebanon spark fears of an all-out conflict.

A vulnerable point for the Indian economy, which imports nearly 85% of its crude oil requirement, is energy security, but experts remained optimistic about global powers stepping in to contain the crisis and limit damage to trade and economy.

With crude oil output of almost three million barrels per day, Iran is a major oil producer and exporter. A fifth of the world's crude oil supply, and 60% of Indian crude oil supply passes through the Strait of Hormuz. A conflict in the region could push up oil prices sharply from the present level of about $72 to a level of $80, said Manoranjan Sharma, chief economist at Infomerics Ratings and former chief economist at Canara Bank. This could worsen India's trade deficit, current account deficit and fiscal deficit.

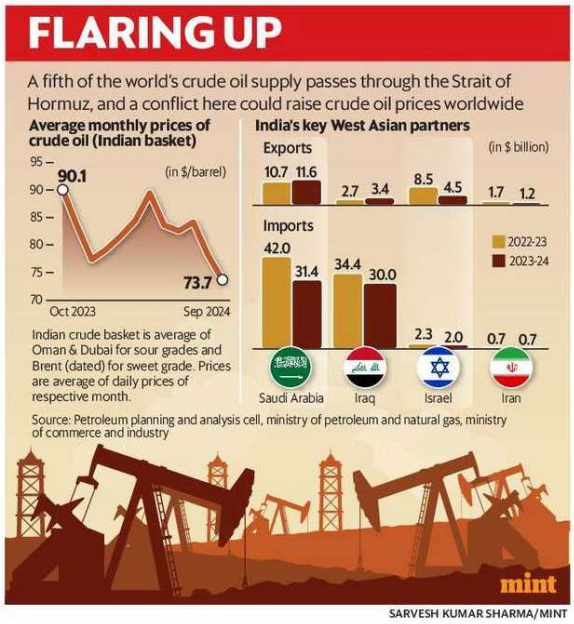

SARVESH KUMAR SHARMA/MINT

The stock market in India could suffer because of the overarching negative sentiment and a discernible element of froth and bubble, Sharma added.

Global GDP and trade growth will be the main casualty, said Devendra Pant, chief economist, India Ratings & Research. This will have an impact not only on India's current account balance but also on the balance of payment, said Pant, adding a strong forex reserve (of over $690 billion as of 20 September) will certainly be helpful.

Exporters believe that if Iran's ports are attacked, outbound essential commodity supplies could get hit. Iran has several ports given its strategic location between Persian Gulf, the Gulf of Oman, and the Caspian Sea.

"The broader impact on international trade routes would be severe, and disruptions to key shipping lanes could significantly hurt global supply chains," said Vijay Kumar Setia, former president of All India Rice Exporters of India (AIREA) and director of Chaman Lal Setia Exports.

Indian exports could suffer due to this conflict, he said. "Many products pass through Iranian ports, and further hostilities could jeopardize not just the rice trade but also trade in a range of Indian goods. The possibility of increased freight costs amid geopolitical tensions, coupled with the ongoing Red Sea challenges, poses serious risks to Indian exporters, already grappling with rising operational costs," Setia said.

However, experts believe that situation is not all that bad, as there are mitigating factors as well.

The flare-up comes at a time when Opec+ is shifting towards higher output, limiting the upside risk to oil prices, inflation and hence interest rates, said Sachchidanand Shukla, group chief economist at Larsen & Toubro Ltd.

"Iran contributes around 4% of global oil output and Saudi Arabia

TURN TO PAGE 11

MINT, Delhi, 3.10.2024
Page No. 1, Size:(16.69)cms X (16.51)cms.

West Asia war could hit India's economy, trade, warn experts

FROM PAGE 1

can also ramp up some production to make up for any shortfall. Moreover, so far, in spite of the West Asian crisis, oil prices have not really moved up on a sustained basis given that major economies—the US, the EU and China have been struggling with lacklustre growth. If the situation is prevented from morphing into a regional war using diplomatic tools, then the disruption to global economy and trade are likely to be contained," said Shukla.

The Indian basket of crude oil comprising both sour and sweet grades, averaged $73.69 in September, down from $78.27 in August and $89.44 in April, according to petroleum ministry data.

The price of Brent crude, a global benchmark, has risen by over $4 a barrel in the last three days. It stood at $75.63 a barrel on Wednesday, up from $73.56 on Tuesday and $71.7 on Monday. In comparison, a year ago, Brent stood at $85.81.

There are other factors that will determine global commodity prices and flow of capital. Going forward, the election outcome in the US and its interest rate trajectory will also shape and determine the pace of recovery in global growth and direction of risk assets and emerging markets including India, said Shukla.

Aditya Narayan Mishra, chief executive of CIEL HR Services, a staffing firm, believes that for the time being, the attractiveness of the West Asia region may come down and that any returning workforce could pose sociological challenges.

"Their wages and living and working habits are different. The workers save up ₹7 lakh a year and send home the money which will not be possible if they return to India," said Mishra, pointing to a potential hit on remittances.

The impact will be visible if the crisis lasts longer than a few days, according to Lohit Bhatia, president of workforce management at staffing company Quess Corp. "West Asia absorbs talent from India in the construction, earth moving and entry levels jobs in auto-manufacturing industry. However, for a short while, there may be a positive impact in similar sectors in India, where workforce is difficult to get," said Bhatia.

West Asia is a key source of oil for India, but after Russia invaded Ukraine, imports from Russia rose due to huge discounts. REUTERS

Energy prices are slowly increasing, but a drastic surge could follow depending on whether Israel targets Iran's nuclear facilities or its oil refineries, with the latter being a more vulnerable and likely target, explained Ram Singh, professor of international business at the Indian Institute of Foreign Trade and head of the Centre for Distance and Online Education (CDOE), IIFT.

Strategic interests, particularly regarding trade routes through Iran, such as the Chabahar port and access to Central Asia and Russia, are also at risk, said Singh.

If the conflict spills over into neighbouring countries, it could result in the closure of the Strait of Hormuz, leading to a global energy crisis and disrupt exports.

Viranchi Shah, president of Indian Drugs Manufacturing Association (IDMA) too expects logistics costs to go up. However, India's volume of pharmaceutical trade with Iran and Israel are limited, said Shah.

In terms of volume, Russia's share in India's oil imports rose from 2% in FY22 to 21.5% in FY23 and over 36% in FY24

West Asia is a key source of oil for India, but after Russia invaded Ukraine in 2022, imports from Russia rose sharply due to the huge discounts on offer.

In terms of volume, Russia's share in India's oil imports rose significantly from 2% in FY22 to 21.5% in FY23 and over 36% in FY24. In contrast, the share of crude petroleum imports from West Asia decreased from 34% in FY22 to 30.9% in FY23 and to about 23% in FY24.

"India faces tough times ahead, particularly for industries reliant on high-volume, low-value exports, as rising freight costs are expected to strain trade further. To navigate these turbulent times, India must stay vigilant and adaptable to the fast-changing geopolitical and trade landscape in West Asia," said Ajay Srivastava, a former India Trade Services official and founder of economic think tank Global Trade Research Initiative (GTRI).

rhik.kundu@livemint.com

Dhirendra Kumar, Priyanka Sharma and Devina Sengupta contributed to the story.

ASSAM TRIBUNE, Guwahati, 3.10.2024
Page No. 12, Size:(24.90)cms X (16.03)cms.

West Asia war escalation may push logistics cost; disrupt oil, electronics, agri trade: Exporters

During January-July 2024, India's trade with countries directly impacted by the conflict has faced significant challenges

NEW DELHI, Oct 2: The escalation of conflict in the West Asian region is expected to push already high logistics costs besides hurting trade in sectors such as oil, electronics and agriculture, according to exporters.

They said that insurance costs for exports to the countries directly involved in the war could also go up, which will impact Indian exporters' working capital.

Think tank Global Trade Research Initiative (GTRI) stated that the conflict is already hurting India's trade with countries like Israel, Jordan, and Lebanon.

The Federation of Indian Export Organisations (FIEO) said the Iran-Israel conflict has the potential to significantly impact world trade and the global economy in several ways. "Iran is a key player in the oil market. Any escalation in conflict could disrupt oil supplies, leading to higher prices, which would impact global economies, especially those reliant on oil imports. Oil prices have already moved up by USD 4 per barrel," FIEO DG Ajay Sahai said.

Expressing concerns, he said increased tensions could destabilize the Middle East, affecting trade routes like the Strait of Hormuz, through which a significant portion of the world's oil passes.

"Disruptions could lead to higher shipping costs and delays. Many global supply chains depend on the stability of the Middle East. Conflict could disrupt transportation and logistics, affecting industries ranging from electronics to agriculture," Sahai said.

Further, if the western world would put sanctions or trade restrictions, it would further complicate the global trade dynamics, he said adding, "Overall, the conflict could lead to increased volatility in global markets".

Hand Tool Association Chairman S C Ralhan said orders to these countries will be on hold and gradually it will be "very risky and difficult" to do trade in this region.

"Insurance costs will go up or even we may not get any insurance cover in that region," Ralhan said. India is Israel's second-largest trading partner in Asia. – PTI

ASSAM TRIBUNE, Guwahati, 3.10.2024
Page No. 1, Size:(24.82)cms X (24.07)cms.

Work on biogas plants begins

STAFF REPORTER

GUWAHATI, Oct 2: Prime Minister Narendra Modi today virtually presided over the ground breaking ceremony of 33 compressed biogas plants across the country. Among them were four key projects in Assam spearheaded by Oil India Ltd (OIL) in Guwahati, Jorhat, Sivasagar, and Tinsukia.

As part of the Government of India's vision for a sustainable energy future, OIL, in close coordination with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, has committed to establish 25 compressed biogas plants by 2024-25, through public sector unit investments or in partnerships with private entrepreneurs.

"This initiative represents a major milestone in India's journey toward a greener, more sustainable future. OIL has developed a strategic plan to diversify into alternative energy, targeting net-zero by 2040, while reaping economic, environmental, and social benefits. By transforming municipal solid waste into compressed biogas, OIL is not only advancing the goals of Swachh Bharat Mission but also fostering a cleaner and healthier environment for all," a statement said.

These compressed biogas plants feature advanced zero liquid discharge systems, ensuring minimal impact on the environment. Each plant is capable of processing 125 tonnes of municipal solid waste from every day. This waste will be converted into approximately 2 tonnes of compressed biogas per day.

The produced biogas can be integrated into the nearest available city gas distribution network or supplied directly to CNG retailers.

The plants are also poised to create significant job opportunities in local communities, spurring economic development and raising the standard of living in these regions.

AMAR UJALA, Delhi, 3.10.2024
Page No. 1, Size:(14.57)cms X (10.57)cms.

इस्राइल का ईरान पर जवाबी हमला किसी भी वक्त, तेल और गैस उत्पादन केंद्र निशाने पर

परमाणु केंद्रों को भी निशाना बनाने की तैयारी | युद्ध के नए मोर्चे की आशंका में भारत ने अपने नागरिकों से ईरान की यात्रा टालने को कहा

नेतन्याहू करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन से बात

तेल अवीव/येरुशलम/नई दिल्ली। इस्राइल कभी भी ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। इस्राइल की मीडिया ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि मंगलवार की रात ईरान की ओर से दागी गईं सैकड़ों बैलेस्टिक मिसाइलों का बदला लेने की रणनीति तैयार हो चुकी है। इस्राइल अब सिर्फ यह तय कर रहा है कि ईरान पर पूरी ताकत से हमला किया जाए या पहले की तरह लक्षित हमलों का सहारा लिया जाए।

इस्राइल टाइम्स ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से लिखा कि जवाबी कार्रवाई में ईरान के तेल व गैस उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाया जा सकता है। योजना ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट करने की है। हालांकि इससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से बात कर इस्राइल की आगे की योजना पर चर्चा करने वाले हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक इस्राइल और ईरान इससे पहले कभी युद्ध के ऐसे मुहाने पर नहीं थे। यहां अगर युद्ध का नया और खतरनाक मोर्चा खुला, तो यह पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगा। इस्राइल के अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने आगे कोई कदम उठाया तो उसके परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया जा सकता है।

इस्राइली हमले की आशंका के मद्देनजर भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। उसने ईरान में रह रहे देशवासियों से सतर्कता बरतने और तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कहा है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि वह क्षेत्र में सुरक्षा हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। एजेंसी

इस्राइल के गेदेरा में ईरान के मिसाइल हमले में स्कूल की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, रेगिस्तानी इलाके अराड में ईरान की मिसाइल के टुकड़े पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते इस्राइली। इसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। एजेंसी

>> लेबनान में घुसी इस्राइली सेना : 14

भारत ने कहा-संवाद और कूटनीति से हल करें मुद्दे : बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की रक्षा करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, सभी मुद्दों को संवाद व कूटनीति के जरिये हल किया जाना चाहिए। इस बीच, पीएम नरेंद्र मोदी ने यहूदी नववर्ष पर इस्राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दी।

बाइडन बोले-परमाणु ठिकानों पर हमले का समर्थन नहीं

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित ठिकानों पर इस्राइल के किसी भी हमले का समर्थन नहीं करेंगे। जी-7 देशों के नेताओं के साथ फोन पर पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा के बाद पत्रकारों से बातचीत में बाइडन ने यह बात कही। बाइडन से चर्चा के दौरान जी-7 नेताओं ने ईरान के हमले की निंदा की। बाइडन ने दोहराया कि वह इस्राइल के पूर्ण समर्थन में खड़े हैं। एजेंसी

इस्राइल ने कहा, यूएन महासचिव अवांछित व्यक्ति, प्रवेश पर रोक

इस्राइल ने ईरान के मिसाइल हमलों की स्पष्ट निंदा न करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। इस्राइल के विदेश मंत्री इस्राइल कात्ज ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि गुटेरस के इस्राइल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ***संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार इस विश्व संस्था के किसी सदस्य देश ने संस्था के प्रमुख के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाया है।***

जिसने हमास, हिजबुल्ला के हमले की निंदा नहीं की, वह यूएन पर धब्बा

कात्ज ने कहा, जो व्यक्ति ईरान के हमले की स्पष्ट निंदा नहीं करता, जैसा कि दुनिया के करीब-करीब सभी देशों ने किया है, वह हमारी जमीन पर पैर रखने लायक नहीं है। वह ऐसे महासचिव हैं, जिन्होंने अब तक बीते साल 7 अक्तूबर को हमास आतंकियों की ओर से इस्राइल में किए नरसंहार और यौन उत्पीड़न की भी निंदा नहीं की है। आज तक हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। ऐसे महासचिव जो हमास, हिजबुल्ला और हूती आतंकियों, दुष्कर्मियों और हत्यारों के अलावा पूरी दुनिया में आतंक की जननी ईरान का समर्थन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास पर धब्बे के रूप में याद रखे जाएंगे।

>> गुटेरस ने की हमले की निंदा : 14

VIRAT VAIBHAV, Delhi, 3.10.2024
Page No. 5, Size:(20.66)cms X (10.70)cms.

आधारशिला यह कार्यक्रम देशभर में सीबीजी के कई संयंत्रों के लिए नींव रखने के समारोह का हिस्सा था।

पीएम मोदी ने चार बायो-गैस संयंत्र की आधारशिला रखी

वैभव न्यूज ■ गुवाहाटी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा चार संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्र के निर्माण के लिए बुधवार को आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम देशभर में सीबीजी के कई संयंत्रों के लिए नींव रखने के समारोह का हिस्सा था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ भारत दिवस के मौके पर एक सतत और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा परिदृश्य को बढ़ावा देना है। असम में ए संयंत्र गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में बनाए जाएंगे। मोदी ने परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद अपने भाषण में कहा, गाय का गोबर हमारे गांवों में बदलाव ला रहा है। भारत के गांवों में अब सैकड़ों बायोगैस संयंत्र बनाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पहले गाय के गोबर का प्रबंधन करना ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब था तथा अगर गाय या बैल अधिक उम्र के कारण या किसी अन्य कारण से अनुत्पादक हो जाएं तो और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन अब इन बायोगैस संयंत्रों के कारण अनुत्पादक गोवंश का गोबर भी हमारे किसानों की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा, शहरीकरण के कारण अपशिष्ट उत्पादन बढ़ रहा है। ई-कचरा जैसे कचरे के नए रूप

भी बढ़ रहे हैं। इस समय, हमें इस समस्या के समाधान के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है। मोदी ने कहा कि भविष्य में मकान निर्माण में पुनर्चक्रण को शामिल किया जाना चाहिए और नए आवासीय परिसरों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि कम से कम कचरा उत्पन्न हो। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि कंपनी की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में निवेश या निजी उद्यमियों के साथ साझेदारी के जरिए 2024-25 तक 25 सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

ऑयल ने कहा, जैसे-जैसे भारत स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनने के अपने दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ रहा है, इन सीबीजी संयंत्रों की स्थापना एक हरित और अधिक लचीले भविष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी सीबीजी संयंत्रों के बारे में कंपनी ने कहा, प्रत्एक संयंत्र हर दिन आसपास की नगरपालिकाओं से 125 टन नगरीय ठोस कचरे को शोधन करने में सक्षम है। इससे यह कचरा हर दिन करीब दो टन सीबीजी में परिवर्तित होगा।

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 3.10.2024
Page No. 9, Size:(14.16)cms X (22.30)cms.

पीएम मोदी ने बायो-सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया

भोपाल (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को स्वच्छता दिवस के अवसर पर ग्वालियर में बायो-सीएनजी संयंत्र वाली 'लाल टिपारा गौशाला' का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने मध्यप्रदेश में 685 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को आरंभ किया।

यह कार्यक्रम देशभर में संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) के कई संयंत्रों के लिए नींव रखने के समारोह का हिस्सा था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ भारत दिवस के मौके पर एक सतत और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा परिदृश्य को बढावा देना है। स्वच्छता दिवस हर साल गांधी जयंती (दो अक्टूबर) के अवसर पर मनाया जाता है। एक अधिकारी ने कहा कि बायो-सीएनजी संयंत्र वाली 'गौशाला' 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन तीन टन प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर सकती है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के सहयोग से स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि यह भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला है। अधिकारी ने कहा कि यह संयंत्र 20 टन उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद का भी उत्पादन करेगा। आईओसी संयंत्र के संचालन और रखरखाव में सहायता करेगा। अधिकारी ने बताया कि गौशाला का निर्माण आईओसी के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से 32 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है तथा इसके विस्तार के लिए एक हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि आरक्षित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छ भारत मिशन' और 'अमृत योजना' के तहत मध्य प्रदेश में 685 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया।

BUSINESS STANDARD HINDI, Delhi, 3.10.2024
Page No. 2, Size:(2.95)cms X (2.88)cms.

'भरोसे पर आधारित है रिलायंस-बीपी का संबंध'

बीपी के निवर्तमान प्रमुख शशि मुकुंदन ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ उनका संबंध अनुबंधों पर नहीं बल्कि भरोसे एवं मजबूत रिश्ते पर आधारित है। दोनों के बीच समझौते की विशिष्ट अवधि भले ही समाप्त हो गई है, लेकिन बीपी मुकेश अंबानी की कंपनी के साथ भारत में तेल एवं गैस व वाहन क्षेत्रों में उद्यम जारी रखेगी। बीपी ने 2011 में रिलायंस के 23 तेल व गैस क्षेत्रों में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी पाने के लिए 7.2 अरब डॉलर खर्च किये थे। *भाषा*

VIRAT VAIBHAV, Delhi, 3.10.2024
Page No. 15, Size:(25.55)cms X (29.86)cms.

मजबूत भरोसे-रिश्ते पर आधारित है रिलायंस-बीपी का संबंध: मुकुंदन

एजेंसी ■ नई दिल्ली

बहुराष्ट्रीय कंपनी बीपी के निवर्तमान प्रमुख शशि मुकुंदन ने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के साथ हमारा संबंध अनुबंधों पर नहीं बल्कि भरोसे और मजबूत रिश्ते पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच समझौते की विशिष्ट अवधि भले ही समाप्त हो गई है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रणनीतिक भागीदारी के तहत मुकेश अंबानी की कंपनी के साथ भारत में तेल और गैस तथा वाहन क्षेत्र में उद्यमों को जारी रखेगी। बीपी ने 2011 में रिलायंस के 23 तेल और गैस ब्लॉक में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 7.2 अरब डॉलर खर्च किए थे। यह पूर्वी अपतटीय केजी-डी6 ब्लॉक सौदे की आधारशिला थी। सौदे के तहत 10 साल की विशिष्ट अवधि का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब था कि बीपी केवल रिलायंस के साथ साझेदारी में ही भारत में ऊर्जा परियोजनाओं या अन्य क्षेत्रों में निवेश करेगी। कंपनी ने अबतक ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में 12 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इसमें केजी-डी6 में गहरे पानी की तीन प्राकृतिक गैस परियोजनाएं शामिल हैं, जो भारत के गैस उत्पादन का एक-तिहाई हिस्सा है। मुकुंदन ने कहा कि हमने 2005 में रिलायंस के साथ काम करना शुरू किया था। जब पहले तत्कालीन बीपी सीईओ लॉर्ड जॉन ब्राउने ने भारत का दौरा किया था, तब हमने भारतीय कंपनी के साथ काम करना शुरू किया। आखिरकार यह 2011 के सौदे में सफल हुआ। उन्होंने कहा, तेल खोज एवं उत्पादन के क्षेत्र में समझौते के 13 साल हो गए हैं, लेकिन हमने एक बार भी पीछे मुड़कर अनुबंध को नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि रिलायंस के साथ साझेदारी अनुबंध पर नही है, बल्कि भरोसा और रिश्ते पर आधारित है। मुकुंदन ने कहा, हमारा संबंध इतना मजबूत है कि जब भी हमारे दोनों साझेदारों के बीच कोई मसला होता है, तो हम बस आमने-सामने बैठते हैं और उसे सुलझा लेते हैं। मुकुंदन ने कहा कि मूल समझौता तेल और गैस खोज और उत्पादन के क्षेत्र में था। लेकिन अब यह बढ़कर खुदरा क्षेत्र में भागीदारी और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों तक पहुंच गया है तथा इस गठजोड़ का आगे और विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा, 2011 में हुए अनुबंध के तहत विशिष्ट व्यवस्था 10 साल के लिए थी। वह अवधि समाप्त हो गई। लेकिन हमारे बीच बिना लिखा-पढ़ी वाला समझौता है... मैं इसे समझौता नहीं कहूंगा, लेकिन यह एक भावना है कि मूल रूप से, हम उनके रणनीतिक भागीदार हैं और वे हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। मुझे लगता है कि दोनों कंपनियां वास्तव में इस पर कायम हैं। मुकुंदन ने कहा, बीपी-रिलायंस का संबंध रिश्ते के दृष्टिकोण से अधिक विशिष्ट हैं। अंबानी के लिए बीपी उसका रणनीतिक साझेदार है।

BUSINESS STANDARD HINDI, Delhi, 3.10.2024
Page No. 4, Size:(26.52)cms X (14.22)cms.

साल के अंत तक जीबीए मुख्यालय पर जोर

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 2 अक्टूबर

भारत और ब्राजील ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) की भौतिक और राजनयिक स्थिति स्थापित करने में देरी पर चर्चा की

भारत और ब्राजील ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) की भौतिक और राजनयिक स्थिति स्थापित करने में देरी पर चर्चा की है, तथा चालू वर्ष के अंत तक दोनों को स्थापित करने की आवश्यकता पर सहमति जताई है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ब्राजील के अपने समकक्ष के साथ ब्रासिलिया में सितंबर में हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी।

नई दिल्ली में हुए जी20 शिखर सम्मेलन के इतर 9 सितंबर, 2023 को जीबीए की शुरुआत की गई थी। लेकिन गठन के एक साल से भी अधिक गुजर जाने के बाद भी इसका चार्टर, स्थायी सरकारी ढांचा या स्थायी सचिवालय नहीं बन पाया है। अधिकारिक सूत्र ने बताया, 'दोनों पक्षों ने जीबीए के लंबित कार्य को तेजी निपटाने के महत्त्व को स्वीकार किया है। मुख्यालय और चार्टर की स्थापना के लंबित कार्य को साल के अंत तक निपटाने के लिए अस्थायी रूप से तिथि तय की गई है।' हालांकि सरकार, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों के बहुहितधारक गठबंधन ने कार्ययोजना को स्वीकार कर लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश के परिदृश्य का आकलन करने, नीतिगत रूपरेखा तैयार करने और जैव ईंधन कार्यशालाओं के आयोजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इन्हें अप्रैल में ब्राजील में जी7 विचार-विमर्श के दौरान आयोजित निकाय की एक प्रमुख बैठक में तत्काल लक्ष्यों के रूप में पहचाना गया था, और जुलाई में जीबीए ने इनका जायजा लिया।

बढ़ती रुचि

जीबीए का उद्देश्य वैश्विक परिदृश्य को बदलना और वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य जैवईंधन के मानदंड तय करना, औपचारिक जैवईंधन के मार्केट का विस्तार और मांग व आपूर्ति को बेहतर करना है। इस 24 देशों के समूह में मुख्य भूमिका भारत और ब्राजील निभा रहे हैं।